(c) For augmenting the country's production of coconut oil Government has set up a Coconut Development Board for promoting coconut cultivation/development. Efforts are being made for improving the production by using modern techniques, i.e. Tissue Culture etc. Remunerative support prices are being announced annually. In order to give thrust for its development, coconut has been declared as an Oilseed. For improving the availability of indigenous, oilseeds, Government is continuing with oilseed production programme, oilseeds projects of N.D.D.B., setting up of Technology Mission on Oilseeds, intensification of research.

आयातित अखबारी कागज का आबंटन

1540. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज की आयात नीति के अधीन 56 प्रतिशत भारतीय और 35 प्रतिशत आयातित अखबारी कागज 200 मीट्रिक टन से अधिक की खपत वाले समाचार-पत्रों को आबंटित किया जाता है;

(ख) क्या यह नियम सरकारी प्रकाशनों पर भी लागू होता है;

(ग) यदि हां, तो 200 मीट्रिक टन से अधिक की वार्षिक खपत वाले "एम्प्लायमेन्ट न्यूज" नामक साप्ताहिक को नियत आयातित अखबारी कागज से अधिक अखबारी कागज आबंटित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इससे विदेशी मुद्रा बचाने की सरकार की नीति पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देशी तथा आयातित अखबारी कागज का अनुपात देश में अखबारी कागज की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। वर्ष 1990-91 के दौरान यह अनुपात 65 : 35 था।

(ख) जी, हां।

(ग) "रोजगार समाचार" को विशेष मामले के तौर पर आयातित अखबारी कागज आबंटित किया जाता है।

(घ) सरकार द्वारा "रोजगार समाचार" का प्रकाशन देश के शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिए किया जाता है। अतः इसका बिक्री मूल्य कम रखा गया है। इस समाचार पत्र के लिए केवल आयातित अखबारी कागज आबंटन भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आयातित अखबारी कागज प्रायः देशी अखबारी कागज की तुलना में सस्ता होता है।

छोटे और मझोले समाचारपत्रों के संबंध में राम मोहन राव समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

1541. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मझोले समाचारपत्रों के संबंध में राम मोहन राव समिति की 27 दिसम्बर, 1990 को सरकार को प्रस्तुत की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किये जा रहे छोटे समाचारपत्रों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सरकार ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की 12 सिफारिशों में से सरकार ने कुछ मामलों में थोड़ा सा संशोधन करने के बाद 11 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। उम्मीद है कि